CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Steep hike in the price of DMS Milk causing immense hardship to the common man

MR. CHAIRMAN: Now, let us take up the Calling Attention. Shri Suresh Pochauri.

श्री रामदेव भंडारी (बिहार) : सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं । बिहार विधान सभा में नीतीश कुमार जी की हार ने इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि बिहार के गवर्नर ने, जो कस्टीट्यूशनल दायित्व उनको दिया गया था, उस दायित्व का निर्वहन नहीं किया है । उन्होंने स्वविवेक का भी पूरा दुरुपयोग किया है । उन्होंने संविधान की मर्यादा, परम्परा और मान्यताओं की अवहेलना की है । महोदय, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि बिहार के गवर्नर को तुरंत वापस बुलाया जाए

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Karnataka) : I am on a point of order ...*(Interruptions)*...

श्री रामदेव भंडारी : सर, मैं... (व्यवधान)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: How can he raise without your permission?...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I have not permitted him...*(Interruptions)*...He has not taken any permission from me...*(Interruptions)*...I have asked for the Calling Attention. You can speak after the Calling Attention is over.

SHRI SANATAN BISI (Orissa): Sir, I am on a point of order...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: What is the point of order?...*(Interruptions)*...

SHRI SANATAN BISI: Sir, my point of order is...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I have already started the Calling Attention ...*(Interruptions)*...This is the time for Calling Attention. The House could not take this up during the whole Session. This is a very important subject. It is on the steep hike in the price of D.M.S. milk. So, people are waiting for this and the whole session has passed.

SHRI SANATAN BISI: Sir, the point of order is allowed if there is any urgent matter...(Interruptions)...A point of order is given to the Members for the purpose of exercising their rights. This is the instrument given to us...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: But the question is the business before the House and the hon. Members is Calling Attention...*(Interruptions)*...Many Members met me in my Chamber and said that this has been pending before the House for a long time...*(Interruptions)*...

SHRI SANATAN BISI: When we raise a point of order, it is the concern of a Member. It is his right. *(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You are right. But I am telling you, now we are taking up the Calling Attention. It is pending there for a number of days.

SHRI SANATAN BISI: Earlier you had said, "You can raise your point of order after the Question Hour is over."...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You can raise your point of order on the issue before the House...*(Interruptions)*...

SHRI SANATAN BISI: Earlier also you said several times in this House that the Members cannot raise a point of order during the Question Hour and they can raise it after the Question Hour is over.

MR. CHAIRMAN: You can raise your point of order on the issue before the House. Now the issue before the House is Calling Attention...*(Interruptions)*...Hon. Members from all sides have been asking for this...*(Interruptions)*...

SHRI SANATAN BISI: Before you took up the Calling Attention, I rose and said that I had a point of order...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I first asked ...*(Interruptions)*... anyway, ...(Interruptions)...

SHRI SANATAN BISI: Sir, allowing a point of order is the prerogative of the hon. Chairman. If the hon. Chairman does not safeguard our rights and interests, we have nothing to say...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Mr. Solipeta Ramachandra Reddy.

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY (Andhra Pradesh): I beg to call the attention of the Minister of Agriculture to the steep hike in the price of D.M.S. milk causing immense hardship to the common man.

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री हुक्मदेव नारायण यादव**): महोदय, जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन के सामने है, उसके संबंध में मेरा निवेदन है कि दिल्ली में दूध की

कुल खपत अनुमानतः 30-32 लाख लीटर प्रतिदिन है और दिल्ली दुग्ध योजना रोजाना लगभग 4 लाख लीटर दूध सप्लाई कर रही है। यह दिल्ली में दूध की कुल आवश्यकता का लगभग 12 प्रतिशत है । मदर डेयरी लगभग 13 लाख लीटर दूध प्रतिदिन सप्लाई करती है जबकि शेष 13 से 15 लाख लीटर दूध प्रतिदिन प्राईवेट डेयरियों द्वारा सप्लाई किया जाता है।

भारत सरकार ने दिल्ली दुग्ध योजना का थैलियों में टोंड दूध और डबल टोंड दूध के बिक्री मूल्यों में संशोधन सितम्बर, 1992 दौरान क्रमशः 7/- रुपए और 6/- रुपए प्रति लीटर किया था । तब से इस वर्ष की पहली मार्च तक, जब थैलियों में टोंड दूध और डबल टोंड दूध के मूल्य में क्रमशः 14/- रुपए और 11/- रुपए का संशोधन किया गया, बिक्री-मूल्यों में कोई संशोधन नहीं हुआ था। इससे दिल्ली दुग्ध योजना के दूध और मदर डेयरी के दूध के बिक्री-मूल्यों में समानता आ गई है। मदर डेयरी को बिक्री मूल्यों में संशोधन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। उन्होंने थैलियों में टोंड दूध के बिक्री मूल्यों में संशोधन करके उसे दिसम्बर, 1994 में 8.50 रुपए प्रति लीटर, फरवरी, 1995 में 9.50 रुपए प्रति लीटर, मई, 1995 में 10.00 रुपए प्रति लीटर, मई, 1996 में 12.00 रुपए प्रति लीटर, जुलाई, 1998 में 13.00 रुपए प्रति लीटर और फरवरी, 2000 में 14.00 रुपए प्रति लीटर किया है। सितम्बर, 1992 से फरवरी, 2000 तक की अवधि के दौरान कच्चे माल के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई। वर्ष 1992-93 में दिल्ली दुग्ध योजना के 6.5 प्रतिशत वसा और 9.0 प्रतिशत वसा रहित ठोस वाले दूध का अधिप्राप्ति मूल्य औसतन 8.72 रुपए प्रति कि.ग्रा. था। जनवरी, 1996 से दिल्ली दुग्ध योजना के कच्चे दूध का अधिप्राप्ति मूल्य मदर डेयरी के कच्चे दूध के अधिप्राप्ति मूल्य के बराबर है । दूध का यह अधिप्राप्ति मूल्य वर्ष 1995-96 में औसतन 10.08 से वर्ष 1996-97 में 10.53 रुपए, वर्ष 1997-98 में 11.30 रुपए और वर्ष 1998-99 में 12.98 रुपए तक बढ़ गया । दूध का वर्तमान अधिप्राप्ति मूल्य 14.00 रुपए प्रति कि.ग्रा. है। दूध की उत्पादन लागत की लगभग 80 प्रतिशत लागत कच्चे दूध का मूल्य है।

सितम्बर, 1992 में जब पिछली बार संशोधन किया गया था, उस समय दूध की उत्पादन लागत मात्र लगभग 7.00 रुपए प्रति लीटर थी जो बढ़कर फरवरी, 2000 में 13.44 रुपए प्रति लीटर तक हो गई है। इससे राजकोष पर आर्थिक सहायता का बोझ काफी हो गया है । पुराने बिक्री मूल्य पर 4 लाख लीटर प्रतिदिन की सप्लाई को बनाए रखने के लिए आर्थिक सहायता की व्यय-सीमा लगभग 8 करोड़ रुपए प्रतिमाह हो गई थी। लिहाजा वित्त मंत्रालय ने कुल मिलाकर वित्तीय अभाव के कारण इस प्रकार की आर्थिक सहायताओं को जारी रखने में अपनी असमर्थता व्यक्त की।

दिल्ली दुग्ध योजना के दूध का बिक्री मूल्य अन्य डेयरियों द्वारा निर्धारित बिक्री मूल्य से लगभग आधा था। इसलिए दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की मांग का दबाव काफी बढ़ गया। समाज का एक हिस्सा, जिसे दि.दु.यो. का दूध नहीं मिल रहा था, असंतुष्ट था। ऐसे असंतुष्ट व्यक्ति काफी बड़ी संख्या में दूध की सप्लाई के लिए दि.दु.यो. से सम्पर्क करते रहे हैं। दूध की काला-बाजारी के बारे में भी काफी आरोप थे।

जून, 1997 में भारत सरकार ने दिल्ली दुग्ध योजना को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया था । उस निर्णय को अभी लागू नहीं किया गया है। हमें विश्वस्त किया गया है कि जब तक दिल्ली दुग्ध योजना के दूध के बिक्री मूल्य में उचित संशोधन नहीं कर दिया जाता, तब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार दिल्ली दुग्ध योजना के हस्तांतरण को मानने के लिए इच्छुक नहीं थी, चूंकि अन्यथा मूल्य वृद्धि की जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को लेनी पड़ती या बहुत ज्यादा आर्थिक सहायता का भुगतान करना पड़ता।

इन सभी परिस्थितियों पर समग्र रूप से विचार करके भारत सरकार ने दिल्ली दुग्ध योजना के थैलियों वाले टोंड दूध और डबल टोंड दूध का बिक्री मूल्य बढ़ाकर क्रमशः 14.00 रुपए और 11.00 रुपए प्रति लीटर करने का निर्णय लिया है जोकि मदर डेयरी के दूध के बिक्री मूल्य के बराबर है। यह भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में दिल्ली दुग्ध योजना अपने दूध के बिक्री मूल्य को मदर डेयरी के बराबर रखेगी। यह आवश्यक है, क्योंकि दिल्ली दुग्ध योजना के दूध का अधिप्राप्ति मूल्य मदर डेयरी के अधिप्राप्ति मूल्य से जुड़ा है । हमें आशा है कि अब दिल्ली दुग्ध योजना का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को हस्तांतरण भी सरल हो जाएगा।

*श्री सोलीपेटा रामचन्द्रा रेड्डी (आंध्र प्रदेश) : हमने मिनिस्टर साहब का ध्यान, तवज्जह डी.एम.एस. के मिल्क प्राइस के हाइक की ओर दिलाया है। बड़ा ताज्जुब होता है, तमाशा भी दिखता है कि मिनिस्टर हमें मदर डेयरी की कहानी सुनाते जा रहे हैं। मदर डेयरी के 1992 में डी.एम.एस. ने रेट फिक्स किये उसके बाद से आज तक रिवाइज नहीं किए, ऐसी बात मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं। उसी तरह से पहले भी मदर डेयरी ने फिर कोई रेट फिक्स किया गया था। उसके बाद 1994 में, 1995 में, 1996में, 1998 में बढ़ाते गए। साथ ही साथ मिनिस्टर साहब यह भी फरमा रहे हैं कि प्रोक्योरमेंट प्राइस भी हम 1995-96, 1996-97, 1997-98, हर साल बढ़ाते गये हैं। मैं आली जनाब मिनिस्टर साहब से जानना

---

*Transliteration of the speech in Persian Script is available in the Hindi Version of the Debates.

चाहता हूं कि आज जो मदर डेयरी की कहानी बोल रहे हैं, जब मदर डेयरी हर साल बढ़ाती जा रही थी, उस वक्त हकूमत का ध्यान उस तरफ क्यों नहीं गया। डी.एम.एस. ने इस ताल्लुक से क्यों नहीं कहा कि प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ता जा रहा है? मैं मिनिस्टर साहब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि जब आपका प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ता जा रहा है तो आप उसके साथ एक रुपया, आधा रुपया सेलिंग प्राइस बढ़ा सकते थे, लेकिन वह नहीं बढ़ाया। मुझे अफसोस के साथ बोलना पड़ता है कि डी.एम.एस. और डी.एम.एस. के आफिसर्ज़ और सरकार 1992 से 2000 तक सब सो रहे थे और आज एक दम जाग उठे कि मदर डेयरी ने दाम बढ़ा दिया, इनको नुक्सान हो रहा है, इस वास्ते बढ़ाना जरूरी है। मैं आपके ज़रिये मिनिस्टर साहब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि दिल्ली की जितनी टोटल दूध की डिमांड है, उसका 12 फीसदी डी.एम.एस. दूध सप्लाई करता है। मैं जहां तक सोचता हूं दिल्ली में रहने वाले गरीब, मजदूर इससे इस्तफाज़ा कर रहे हैं, आज एक-दम सात रुपये से बढ़ा कर 14 रुपये करना ज़रा ज्यादती दिखता है । मैं समझता हूं कि न सिर्फ हिन्दुस्तान में बल्कि पूरी दुनियां में कहीं भी इतना स्टीप हाइक नहीं हुआ होगा । आप 7 रुपये से बढ़ा कर, 8 रुपये, 9 रुपये या 10 रुपये कर सकते थे, फिर 4-6 महीने के बाद और बढ़ा सकते थे । लेकिन एकदम जाग कर 7 रुपये से 14 रुपये करना ज़रा ज्यादती है । जहां तक दूध की बात है, दूध का इस्तेमाल कई किस्म से होता है और हर फेमली और हर मकान में दूध का इस्तेमाल होता है । शायद ही ऐसा कोई परिवार या मकान होगा जहां दूध का इस्तेमाल नहीं होता । खसूसन बड़े लोग जो अच्छे मालदार लोग हैं वह कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं, कहीं से भी दूध ले सकते हैं लेकिन गरीब लोग, मिडल क्लास के लोग ज्यादातर डी.एम.एस. के दूध पर आधारित रहते हैं। 7 रुपये से एकदम 14 रुपये बिलकुल मुनासिब नहीं है, नावाजिब है, ज्यादती दिखता है । मैं इन तमाम बातों को सुनने के बाद मदर डेयरी की बात, प्रोक्यारेमेंट प्राइस की बात सुनने के बाद भी मिनिस्टर साहब से यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, डिमांड करना चाहता हूं कि 14 रुपये करना, स्टीप हाइक करना बिलकुल गलत है, नावाजिब दिखने वाली बात है, दुनियां में देखने वालों के लिए बहुत बुरी चीज़ दिखाई देती है । इस वास्ते मेहरबानी कर के दिल्ली में रहने वाले गरीब और मिडल क्लास के लोगों की हार्डशिप्स को मद्दे नज़र रखते हुए 14 रुपये से घटा कर 9 रुपये दूध का रेट रखना चाहिये । इससे ज्यादा नहीं करना चाहिये यह रिक्वेस्ट करते हुए मैं आपसे इजाजत लेता हूं।

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : माननीय सभापति जी, दिल्ली में दूध की कुल आवश्यकता का लगभग 12 प्रतिशत दूध डी.एम.एस. द्वारा सप्लाई किया जाता है। इसलिए डी.एम.एस. के दूध के दाम में जो दुगनी वृद्धि की गई है, उसका निश्चित रूप से असर

दिल्ली वासियों पर पड़ा है । जो गरीब बच्चे दूध का सेवन करते हैं, उनके पालन पर भी इसका एक विपरीत प्रभाव पड़ रहा है । इसलिए चारों तरफ से यह मांग हो रही है कि मूल्य वृद्धि का जो सरकार ने निर्णय लिया है, उसको तुरंत वापिस लिया जाना चाहिये क्योंकि अभी तक के जो आंकड़े हैं और अगर पुरानी बातों को हम लोग उठा कर देखें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इससे पूर्व में कभी भी डी.एम.एस. के द्वारा जिस दूध की बिक्री होती है, उसके दाम में कभी भी दुगनी वृद्धि नहीं की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि यह जो कदम सरकार ने उठाया है, यह पश्चिमी देशों के दबाव में उठाया है बल्कि यह कहूं तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि दूध के दाम में दुगनी वृद्धि कर के पश्चिमी देशों के सामने इस सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया है जिसकी वजह से दिल्ली के लाखों गरीब बच्चे, जो दूध का सेवन करते हैं, उनके मुंह से दूध छिनेगा ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बिंदु 6 में जिस बात का उल्लेख किया है कि जून, 1977 में भारत सरकार ने दिल्ली की दुग्ध योजना को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया था तो मैं आपके माध्यम से विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि उस समय दिल्ली में जो सरकार थी वह विरोधी पार्टी की सरकार थी, गैर-कांग्रेसी सरकार थी और वह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने यह बहुत ही कटु और कड़वा निर्णय उस समय लिया था। मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दूध के दाम में जो वृद्धि की है वह इस प्रकार का कदम है कि एक तरफ तो लोगों को रोजी रोटी का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ लोगों को दूध भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी का उदारीकरण पर आधारित आर्थिक नीतियों संबंधी जो चेहरा है वह बेनकाब हुआ है। ऐसा मैं मानकर चलता हूं क्योंकि जो टोटल आवश्यकता है दिल्ली में दूध की वह लगभग 30-32 लाख लीटर प्रतिदिन के करीब की है और उसमें 12 प्रतिशत जो खपत होती है वह डी.एम.एस. के द्वारा होती है। इसलिए डी.एम.एस. के द्वारा दूध के दाम में वृद्धि किया जाना अपने आप में एक बहुत ही अनुचित कदम है। इसका प्रभाव दिल्ली के गरीब लोगों पर पड़ रहा है, उन गरीब बच्चों पर पड़ रहा है जो दूध का सेवन करके ही अपनी जिन्दगी का पालन पोषण कर रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से कि यह सरकार, दूध के दाम में जो दुगनी वृद्धि की गयी है उसके बारे में न सिर्फ पुनर्विचार करे बल्कि इस मूल्य वृद्धि को तुरंत वापस ले ताकि गरीब बच्चों को दूध मिल सके। ये ऐसे गरीब बच्चे हैं जो शाकाहारी भोजन में विश्वास करते हैं। ये ऐसे गरीब बच्चे हैं जो दूध के सहारे ही अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं। ये ऐसे गरीब बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा तादाद में दिल्ली में हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि डी.एम.एस. के दूध के दामों में जो दुगनी वृद्धि की गयी है उसको वापस किया जाए। बहुत

बहुत धन्यवाद।

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): Sir, as far as milk production is concerned, mostly women, particularly widows, are engaged in it with loans provided by the Government. The reason given here is:

> "Currently the procurement price is Rs.14/- per kilogram. Nearly 80% of the cost of production of milk is the cost of raw material."

> "There is surplus production in Tamil Nadu. In fact, since it is surplus, the Government is procuring milk only on five days in a week, and on the rest of the two days, it is not procuring it. There was an agitation in Tamil Nadu by milk producers. They want that the Government should procure the entire milk. I am requesting the Government to procure the surplus milk from Tamil Nadu and supply it to the DMS at a low rate."

The increase from Rs.7/- to Rs.14/- is alarming. That can be reduced to a great extent if the surplus milk available in other parts of the country is procured and given to people in Delhi.

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): Sir, ...

MR. CHAIRMAN: Your party has already spoken.

SHRI VAYALAR RAVI: This is an important issue. That is why I wanted to speak.

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : धन्यवाद सभापति महोदय।

सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उस वक्तव्य को देखकर मुझे कविता की पंक्तियां याद आती हैं -

> 'खूबसूरत बहानों की जंजीरों में बंदी हमारे दोस्त, तुम न आते हमारे गांव, पर यह भी जिंदगी तो देख जाते'

तो महोदय, मैं जिस जिंदगी की चर्चा कर रही हूं, दुर्भाग्य से आज सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व वाणिज्य संगठन और विश्व बैंक के नुस्खों को तोते की तरह भारतीय परिस्थितियों में उल्था कर रहे हैं। हमारे देश की जनता के दुखदर्द, उसकी

पीड़ा से उनका कोई सरोकार नहीं है। डी.एम.एस. के दामों में वृद्धि उसका एक ज्वलंत प्रमाण है।

सभापति जी, मंत्री जी ने जो तर्क दिए हैं, मैं उन तर्कों से असहमत हूँ क्योंकि इस सरकार के लिए बड़े लोगों के सारे दरवाजे खुले हैं-बहुराष्ट्रीय कंपनियों और पूंजीपतियों के लिए दरवाजे खुले हैं। आप का पूरा बजट और आप की आर्थिक नीतियाँ इस बात की गवाह हैं कि हमारे इस लोकतांत्रिक देश में आज जो सरकार चल रही है और पिछले 10 वर्षों से जिन उरदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों को चला रही है, उन नीतियों के चलते आज लोक कल्याणकारी राज्य की हमारी भूमिका खत्म होती जा रही है। सभापति जी, मैं मंत्री जी से और विशेषकर सरकार से कहना चाहूँगी कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वह रास्ता न सिर्फ हमारे बच्चों के मुँह से दूध छीन रहा है बल्कि हिंदुस्तान की गरीब जनता से रोटी छीन रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी बात कह रहे हैं कि हमें इसकी समीक्षा करनी होगी, लेकिन साथ ही, हमारे गणतंत्र के 50 वर्ष के कार्यक्रम में राष्ट्रपति महोदय ने चेतावनी दी थी कि उरारीकरण के इस रास्ते पर चलते हुए जिस तेज रफ्तार से आप भाग रहे हैं, उसमें पैदल चलने वाले आदमी को मत भूलिए। मगर हमारी सरकार गरीब जनता को भूल गई है। क्या आपने कभी यह मुआयना किया कि इन आर्थिक नीतियों के चलते पिछले 10 वर्षों में कितने और लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं? क्या आपने समीक्षा की है कि आपकी आर्थिक नीतियों के चलते देश के उद्योग-धंधे लगातर बंद होते जा रहे हैं? महोदय, विश्व बैंक ने खुद यह बात कही है कि उदारीकरण के नुस्खे फेल होते जा रहे हैं, लेकिन आप उन्हीं नीतियों पर चल रहे हैं। महोदय, वित्त मंत्री ने इस देश को कौन सा बजट पेश किया है? आप उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी कर रहे हैं, तटकर शुल्क में कमी कर रहे हैं, सब्सीडियों में कटौती कर रहे हैं, पी.डी.एस. व्यवसथा खत्म कर रहे हैं किस लिए? जबकि हिन्दुस्तान जैसे देश में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की जरूरत है। जहाँ 90 फीसदी से अधिक लोगों को पी.डी.एस. की जरूरत है, वहाँ हमारी सरकार कह रही है कि गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहने वालों के लिए गेहूँ, चावल का कोटा बढ़ा दिया है, लेकिन आपने गेहूँ, चावल के दामों में दोगुनी वृद्धि कर दी है। आप गरीब जनता के मुँह से रोटी का निवाला छीन रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा बजट बहुत अच्छा है। मैं पूछती हूँ कि आपके बजट की क्या दिशा है? मैं मंत्री जी से कहूँगी कि आप दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की कीमत में हुई वृद्धि का प्रभाव जाकर देखिए। लोगों ने आप के दूध के उन कंटेनर्स को लौटा दिया है और आप कह रहे हैं कि चूंकि दूध का लागत मूल्य बढ़ गया है, इसलिए हमारे पास कीमत बढ़ाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। मैं पूछती हूँ कि आप उदारीकरण की नीतियों के चलते छूट किस को दे रहे हैं? रिजर्व बैंक के कानून में तब्दीली की जा रही है, पूंजीपतियों को छूट दी जा रही है, सट्टेबाज पूंजी

को खेलने की पूरी छूट दी जा रही है। इसलिए मंत्री जी, आप का यह तर्क बिल्कुल ही हमारे गले के नीचे नहीं उतरता। आप क्यां नहीं प्रत्यक्ष करों में बढ़ोतरी करते ? आप उर्वरक के दाम में क्यों बढ़ोतरी कर रहे हैं? महोदय, हिंदुसतान की जनता के बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि, 'हिन्दुस्तान की आत्मा गांवों में रहती है और अगर हिंदुसतान का विकास होना है तो पहले गांवों का विकास होना है। महोदय, यह सरकार उन तमाम नीतियों को भूल गयी है बल्कि उन तमाम नीतियों को उल्टा कर के बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित में सारी-की-सारी नीतियाँ अपना रही है। आप की इन जन-विरोधी नीतियों के चलते हमारे देश का जनतंत्र कमजोर हो रहा है, लोकशाही कमजोर हो रही है क्योंकि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से लगातार भाग रही है और उसने एकमात्र 'रामबाण' नुस्खा निजीकरण का अपना लिया है जिसके चलते देश के तमाम उद्योग, जो कि मुनाफे में चल रहे हैं, आप उनका भी निजीकरण करने की बात कर रहे हैं। देश की जनता गरीबी, बेरोजगारी से पीड़ित है और हमारी सरकार उन तमाम नीतियों को अपना रही हे जिससे कि जनता को रोजगार न मिले। महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी विकास की बात कर रहे हैं, मैं पूछती हूँ कि देश में कौन-सा विकास हो रहा है? सिर्फ जॉबलेस ग्रोथ हो रही है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार जिन गलत नीतियों, जन-विरोधी नीतियों को अपना रही है, दूध की कीमत में वृद्धि उसकी इन्हीं नीतियों का ही नतीजा है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगी कि आप हमारे उन बच्चों की ओर भी देखें, उन गरीब लोगों का भी ध्यान रखें। मैं पूछती हूँ क जब आप इन लोगों की सब्सिडी में कटौती करते हैं तो क्या आप के पास बड़े लोगों की सब्सिडी में कटौती करने के रास्ते नहीं हैं? आप प्रत्यक्ष कर क्यों नहीं बढ़ाते? महोदय, हिंदुस्तान में सबसे कम प्रत्यक्ष कर है। क्यों आप उन तमाम चीजों के बारे में कदम नहीं उठाते? इसलिए, सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इस जनविरोधी कदम को वापिस लें क्योंकि यह हमारे बच्चों के साथ, गरीब लोगों के साथ एक खिलवाड़ है और इसके विरोध में दिल्ली की जनता सड़कों पर उतर आई है, आप इस दिल्ली की जनता की आवाज को सुनिए। आपने आलू और प्याज़ के दामों पर जनता की आवाज़ को नहीं सुना, क्या नतीजा हुआ था? अब अगर दूध के बढ़े हुए दामों पर भी आपने दिल्ली की जनता की आवाज़ को नहीं सुना तो इसका नतीजा क्या होगा, वह भी आप जरूर समझेंगे। इसलिए मैं कहूंगी कि आप दूध के इन बढ़े हुए दामों को वापिस लीजिए और जनता को राहत दीजिए। धन्यवाद।

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, इस सरकार की व्यापक नीतियों से दिल्ली दुग्ध योजना के दूध के जो दाम बढ़ाए गए हैं, उससे भले ही हम संबंध न रखते हों

लेकिन यह बात सही है कि जो इस सरकार की नीति है, नीयत है, वह कल्याणकारी राज्य के विरोध में है, हिन्दुस्तान के गरीबों के विरोध में है और वह देश के बड़े लोगों के हित में है और इसी आधार पर इनकी नीतियां चल रही हैं और इसमें थोड़ा-बहुत संबंध इनकी नीयत की वजह से, इनकी मंशा की वजह से जरूर लगता है।

श्रीमन्, कल्याणकारी राज्य की कल्पना में तो हमने ऐसा भी सुना है कि यूरोप वगैरह में दूध के या किन्हीं ऐसी चीजों के दाम जब बढ़े हैं या बढ़ते हैं और वहां यदि सरकारी डेयरी नहीं होती और प्राइवेट डेयरी के दाम यदि बढ़े हैं तो भी सरकार ने उपभोक्ताओं को उतने ही पैसे में दूध दिलवाया है, जितने पैसे में पहले उपभोक्ताओं को मिलता रहा है और बाकी का जो पैसा उसमें बचता था, जो बढ़ता था, उसकी पेमैंट वहां की सरकार करती थी । यह कल्याणकारी राज्य की कल्पना होती है । यह कल्पना इस सरकार में नहीं रही। ठीक है, अगर दूध के दाम बढ़ाने ही थे, इसमें कोई बहुत अधिक कहने की बात नहीं है, तो सरकार को कम से कम यह तो सोचना चाहिए था कि दुनिया में या देश में कभी भी, किसी भी वस्तु के दाम एक साथ इतनी रफ्तार से नहीं बढ़ाए जाते कि वे दुगुने कर दिए जाएं। ठीक है, अगर कोई ऐसी समस्या थी तो थोड़े-बहुत दाम बढ़ाते - 8 रुपए करते, 9 रुपए करते, 10 रुपए करते।

हम सरकार से इतना ही अनुरोध करेंगे कि वह कल्याणकारी राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए काम करे और उसने जो यह 14 रुपए प्रति किलो दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की कीमत रखी है, उसको कम करे, 10 रुपए कर दे तो बड़ा हितकारी होगा और कल्याणकारी राज्य की कल्पना साकार होगी । धन्यवाद ।

श्रीमती सरोज दुबे (बिहार) : सभापति महोदय, मैं यह नहीं समझ पा रही कि भारतीय जनता पार्टी की यह केन्द्र सरकार पता नहीं क्यों मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के तबके के मुंह से रोटी का कौर छीन लेना चाहती है, उनकी सब सुख-सुविधा छीन लेना चाहती है और यहां तक कि बच्चों के मुंह से उनका दूध छीन लेना चाहती है। यह गरीब देश है, यहां पर बच्चों को भरपेट दूध तो नहीं मिलता, लेकिन कुछ सस्ता दूध मिल रहा था और एक घूंट दूध पिलाकर ही मां बड़ी संतुष्टि का अनुभव करती थी और कभी बच्चा जब बीमार हो जाता था तो बाजार से एक छटांक दूध खरीदकर उसको पिला देती थी। लेकिन भारत सरकार से यह भी न देखा गया और उन्होंने दिल्ली दुग्ध योजना के दूध के मूल्य में दुगुनी वृद्धि करके दुधमुंहे बच्चों को एकदम मौत के रास्ते पर खड़ा कर दिया। एक ओर तो कहा जाता है कि सारे बच्चों का स्वास्थ्य ठीक किया जाएगा, स्वास्थ्य की योजनाएं चलाई जा रही हैं और दूसरी ओर एक बहुत ही साधारण सा जो उपाय था कि बच्चे अगर दूध पीएंगे तो उनका स्वास्थ्य

ठीक होगा, उस दूध के दाम बढ़ाकर उस उपाय को समाप्त किया जा रहा है। महोदय, यह एक बहुत ही क्रूर कदम है, सरकार का बहुत ही निर्दयी कदम है और देश के नौनिहाल, जो कल को इस देश को संभालेंगे, यह उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का काम है और यह एक स्वास्थ्यविरोधी, बालविरोधी और समाजविरोधी अभियान है।

महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि सरकार हर समय इस प्रयास में लगी रहती है कि किस तरह से देश के जो दिनभर मेहनत करने वाले लोग हैं, जो देश के खेत-खलिहान को भरते हैं, जो दिनभर कंधे पर बोझा ढोते हैं, रिक्शा खींचते हैं, ठेला खींचते हैं, उनकी और उनके बच्चों की सुविधाओं में किस प्रकार कटौती की जाए और यही कारण है कि चाहे वे राशन की चीजें हों, खाने की चीजें हों, चाहे वह डीज़ल की बात हो, हर चीज़ के मूल्य में वृद्धि हो रही है। इस तरह एक तरफ तो गरीबों का पेट काटा जा रहा है और दूसरी तरफ अमीरों के लिए बड़े-बड़े सुख और ऐश्वर्य के साधन मुहैया किए जा रहे हैं । तो मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहती हूं कि यह आपका बहुत ही गलत कदम है और बहुत ही निर्दयी कदम है। इस देश का बच्चा, मध्यम वर्ग का बच्चा, गरीब वर्ग का बच्चा अगर एक घूंट दूध के साथ बासी रोटी खाकर स्कूल जाना चाहता है तो उसके मुंह से वह दूध का एक घूंट मत छीनिए। महोदय, गरीब या मध्यम वर्ग का आदमी अपने बच्चों को एक-दो किलो दूध नहीं पिलाता है। वह तो एक छटांक या 100 ग्राम दूध से अपने घर का काम चलाता है और चाय पिलाकर काम चलाता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि दूध का जो दाम आपने बढ़ाया है, इसको आप तुरंत वापस ले लें और इससे पहले कि दिल्ली के बच्चे सड़कों पर आएं, पहले ही कुछ बच्चे सड़कों पर आ चुके हैं - इससे पहले कि दिल्ली के बच्चे सड़क पर आकर आपके सामने अपने खाली पेट बजाएं और इससे पहले कि दिल्ली के बच्चों का स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो जाए, उनकी हड्डियां कमजोर होकर उनको रिकेट्स या सूखा रोग हो जाए, आप अपने इस कदम को वापस ले लीजिए और दूध के दाम कम कर दीजिए।

महोदय, मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहती हूं कि आप और चीजों में दाम बढ़ाइए, आप प्रत्यक्ष कर बढ़ाइए, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आप केवल गरीबों पर वार करना चाहते हैं। आपका यह कदम गरीब विरोधी है, समाज विरोधी है और इसको महिला विरोधी भी कहा जाएगा क्योंकि जब बच्चे को दूध नहीं मिलेगा तो सबसे ज्यादा तकलीफ मां को होगी, सबसे ज्यादा तकलीफ बहन को होगी । इसलिए आप इस महिला विरोधी कदम को वापस लीजिए और दूध के दाम कम करके एक बार फिर से बच्चों के चेहरे पर लाली ला दीजिए, बच्चों के चेहरे पर खुशहाली ला दीजिए जिससे कि आने वाले दिनों में जो देश के भावी नागरिक हैं वे तंदुरुस्त हों और अच्छे नागरिक बनकर देश की बागडोर संभालें ताकि आने वाले दिन खुशहाली के हों और प्रगति की राह पर बढ़ने वाले हों। धन्यवाद।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, दूध के बढ़े दामों को लेकर इस सदन में वर्ल्ड बैंक से लेकर भुखमरी तक और गेहूं और चावल के दामों से लेकर कौन-कौन से विषय नहीं आए, यह हमने अभी देखा। यह बताया जा रहा है कि गरीब बच्चों के मुंह से दूध छीना जा रहा है । वास्तविकता तो यह है कि मैं संसद सदस्य हूं, मैं 7 रुपए किलो दूध लेता था। तो यह चोट सांसदों को भी लगी है । इस बात को क्यों नहीं उजागर किया जा रहा है? गरीबों की बात तो बाद में होगी, अपनी बात भी करनी चाहिए। इसीलिए सबसे ज्यादा चोट लगी है ...(व्यवधान)

श्रीमती सरोज दुबे: गरीबों की बात करिए, मध्यम वर्ग की बात करिए ।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल: महोदय, वास्तविकता यह है कि जिस वक्त मैं संसद सदस्य बना था 1998 में और मैंने दिल्ली में फ्लैट लिया तो मुझे पता चला कि यहां 7 रुपए किलो दूध मिलता है जब कि बाजार में इसकी कीमत 12 रुपए किलो है । तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था कि 7 रुपए किलो दूध कैसे मिल रहा है और वह भी जितना चाहिए, उतना मिल रहा है । हमसे कहा गया कि आप 20 लीटर लिख दीजिए, बाकी दूध दूसरे लोग ले लेंगे। तो बाज़ारता ब्लैक हो रहा था इस बूथ पर और उसको पकड़ने में सरकार सर्वथा असमर्थ रही है । महोदय, जो बात सच्चाई की है, उसे कह देना मैं वाजिब समझता हूं।

महोदय, मेरा अंतिम निवेदन यह है कि इस सदन में हर सब्सिडी की कटौती पर टिप्पणी होती है, बड़ी लानतें-मलामतें दी जाती हैं । कृपा करके सदस्य यह भी बताएं कि इन सब्सिडीज़ को कहां से पूरा किया जाए? सरकार तो चाहेगी कि 2 रुपए किलो दूध दे दे लेकिन बाकी रुपया कहां से आएगा? उसके लिए भी तो माननीय सदस्य सुझाव दें। जब माननीय सदस्य एक स्पैसिफिक कटौती की बहाली की मांग करते हैं तो स्पैसिफिक सुझाव दे दें कि यह पैसा कहां से आएगा । यह देश जितना हमारा है, उतना यहां बैठे हुए सभी सदस्यों का है। हम सबको इसकी चिंता करने की भी आवश्यकता है, इतना ही मुझे कहना है।

SHRI VAYALAR RAVI: Mr. Chairman, Sir, I am on a point of order. A Call-Attention has been tabled and the hon. Chairman, in his wisdom, has admitted it. It is an urgent and important matter which concerns the people. Now, is it permissible for any Member to speak against the whole motion? Even on a Bill, I am not expected to move an amendment which will negate the whole process of law. Likewise, the Call-Attention is meant to express the grievance of the people. Members may speak positively. Of course, the Minister can very well say that, refute it. But, is a Member allowed to speak against the whole spirit of the Call-Attention motion? It is a very serious matter, Sir.

MR. CHAIRMAN: There is no point of order in this. Mr. Azmi.

*मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी (बिहार): सदर साहब, दूध के मसले पर हाऊस में जो बहस हो रही है यह चिंता वाकई काबिल तशवीश है। सात रुपए किलो दूध को चौदह रुपए किलो कर देना मेरी खुद समझ में बात नहीं आती कि सरकार की आखिर यह कौन सी हिकमते अमली है। हर सरकार जो गरीबों के मसायल से जुड़ी होती है, कोशिश इस बात की करती है कि जो चीज गरीबों में आती जाती है उस चीज में कम से कम कीमत को ज्यादा किया जाए ताकि गरीब की आह न पड़े और गरीब का रिएक्शन न आए। इसमें कोई शक नहीं है कि दूध को सात रुपए किलो के बजाय चौदह रुपए किलो किया जाना कहीं से भी अखलाक़ी तौर पर, इंसानी तौर पर और खुद हुकूमत के मफाद में नहीं है। हुकूमत को यह कीमत किसी और चीज में बढ़ानी चाहिए थी, इस चीज का ताल्लुक सीधे-सीधे गरीब और अमीर सब से है। जहां तक हमारे मि. सिंहल साहब ने कहा है कि एम.पीज. भी प्रभावित हुए हैं। मैं उनकी इस बात से मुत्तफिक़ तो हूं मगर चूंकि हम मेम्बरान पार्लियामेंट गरीबों के नुमाइंदे हैं और हमारी लड़ाई गरीबों के लिए होती है इसलिए मैं इस सिलसिले में यहां पर अपनी बात कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि गरीब की बात बाद में होगी...(व्यवधान) सुन लो, थोड़ा सा तो बोल लेने दो। मालूम है कि आप नहीं बोलने देंगे।...(व्यवधान)

मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं कि हम अपने देश की जनता के नुमाइंदे हैं, जनता की तकलीफ को आपके सामने रख कर हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि या तो दूध की वही कीमत रहने दें या ज्यादा से ज्यादा अगर बढ़ाने की या गरीबों के ऊपर गरानी लादने की आदत ही हो गई है तो एक रुपए से ज्यादा इसको बढ़ाने की कोशिश न करें और मैं मेम्बराने पार्लियामेंट की तवोज्ज़ह दिलाऊंगा कि हम तमाम मेम्बराने पार्लियामेंट को चाहिए कि हम यह दूध लेना बंद कर दें उस अवाम के लिए जिस अवाम की गरीबी का रोना यहां रोया जा रहा है। हमको दूध नहीं चाहिए मगर उन गरीबों को सात रुपए किलो दूध जरूर दिया जाना चाहिए जिन गरीबों का खानपान दाल मीट के बिना इसी दूध और रोटी से चलता है। आपके माध्यम से दरख्वास्त करता हूं कि हुकूमत अवाम पर, जनता पर रहम करे और अगर हमारे मामलात में कोई कटौती हो सकती हो तो हम इसके लिए तैयार हैं, वह बोझ हमारे ऊपर डाल दिया जाए, गरीब जनता के ऊपर न डाला जाए।

कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): श्रीमन्, सरकार ने प्रयास किया है कि एक छोटी सी विसंगति चल रही है काफी लम्बे समय से तो उसको दूर कर दिया

---

* Transliteration of the speech in Persian Script is available in the Hindi Version of the Debates.

जाए।...**(व्यवधान)** मेहरबानी करके मैं आपके सदन में नया-नया हूं, एकाध बार मुझे शांति से सुन लें तो बड़ी कृपा होगी।

आपको पहले धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने एक अच्छा विषय उठाया और सरकार को अपना पक्ष साफ करने का मौका दिया।...**(व्यवधान)** महिलाओं को चुप रखना बड़ा मुश्किल है।...**(व्यवधान)**

***मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी**: घर से ज्यादा तंग नजर आ रहे हैं आप।...**(व्यवधान)**

श्री सुन्दर लाल पटवा : श्रीमन्, केवल चार लाख लीटर दूध को दिल्ली दुग्ध योजना से उपलब्ध करवाया जा रहा था और तेरह लाख मदर डेरी से, जो भाव बढ़ाती रही है इसे सरकार ने नहीं बढ़ाया है, धीरे-धीरे भी नहीं बढ़ाया है। आपके इस तर्क से मैं सहमत हूं और इसको स्वीकार करता हूं कि अगर सरकार ने नही बढ़ाया तो गलत किया है। इसीलिए आज एकदम बढ़ा देने का आरोप हमें झेलना पड़ रहा है। मैं यह कह करके अपना बचाव नहीं करना चाहता कि हम उस समय सरकार में नहीं थे, सरकार सरकार होती है। सुरेश पचौरी जी भाषण देकर चले गए कि हमने गरीबों के मुंह का निवाला छीन लिया।

सभापति महोदय, अपनी लोक सभा का और एनेक्सी का जो बूथ है उस पर 6,000 लीटर दूध प्रतिदिन सप्लाई होता था। जब से दूध की कीमत 7 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये लीटर की है उसके बाद से उसकी मात्रा 6,000 लीटर से घटकर तीन सौ लीटर प्रतिदिन रह गई है। मैं सोचता हूं कि यहां से गरीब बच्चे दूध लेकर नहीं जाते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री संघ प्रिय गौतम : सभापति महोदय, ...**(व्यवधान)**...

***मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी** : सर, गौतम जी को एडवाइज मिनिस्टर बना दिया जाए। ...**(व्यवधान)**... गौतम जी सुनने दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सुन्दर लाल पटवा : हमारे पचौरी जी ने तो इस डेयरी का सात रुपये लीटर का दूध नहीं पीया होगा, उनका आकार बता रहा है। वह इस समय यहां पर नहीं हैं। वे मेरे परम मित्र हैं, उनको क्या जवाब दूं। हम वैश्वीकरण के दबाव में आ गए, हम विदेशी ताकतों के हस्तक बन गए, हम मल्टीनेशनल के दबाव में आ गए, पता नहीं कौन-कौन से आरोप

---

* Transliteration of the speech in Persian Script is available in the Hindi Version of the Debates.

लगाने का मौका माननीय सदस्यों को मिल गया और बहन सरला माहेश्वरी का तो पूरा बजट भाषण मैंने दूध पर सुन लिया। ...(**व्यवधान**)... आपने बहुत अच्छा कहा है, मैं तारीफ करता हूं। ...(**व्यवधान**)...

***मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी** : सर, आप हम लोगों को भी खूब सुनाइये, लेकिन दूध के दाम कम कर दीजिए। हम लोगों का भी दूध बंद कर दीजिए। अगर आप गरीबों के हित में हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सुन्दर लाल पटवा : हम गरीब विरोधी हो गए, हम सरकार में बैठे हैं, कैसे बैठे हैं बहन सरला जी को आश्चर्य हो रहा है। आखिर 50 साल हमने भी गरीबों के बीच में रहते हुए गुजारे हैं।

सभापति महोदय, एक छोटी सी बात का बतंगड़ कैसे बनाया जाता है, यह सारी बहस में मैंने सुना, माफ करें। एक जगह पर चार लाख लीटर दूध सात रुपये लीटर मिल रहा है और 13 लाख लीटर दूध सारे बाजार में मदर डेयरी 14 रुपये लीटर बेच रही है। पहले 4 लाख लीटर दूध की सप्लाई होती थी, लेकिन जब से इसके दाम बढ़ाये हैं दूध की सप्लाई की मात्रा घटकर लगभग ढाई लाख लीटर रह गई है। ...(**व्यवधान**)...

श्री ललित भाई मेहता (गुजरात): प्राईवेट लोग तो दूध इससे भी ज्यादा दाम पर बेचते हैं। ...(**व्यवधान**)...

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी : 14 रुपये के बजाय 20 रुपये कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। आप कम से कम अवाम की हमदर्दी में बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी: डीएँमएस को ताला लगवा दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सुन्दर लाल पटवा: माननीय सदस्यों को जितना दर्द गरीबों के लिए है, उससे कम हमको है ऐसा आप क्यों मानते हैं? ...(**व्यवधान**)...

***मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी**: हमें यकीन है कि जो दाम आपने दूध के बढ़ाये हैं वह आप वापस ले लेंगे। ...(**व्यवधान**)...

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : सभापति महोदय, यह जो बार-बार इंटरफेयर हो रहा है क्या यह मर्यादा के अनुकूल है? ...(**व्यवधान**)...

---

* Transliteration of the speech in Persian Script is available in the Hindi Version of the Debates.

श्री सुन्दर लाल पटवा : जब आज़मी साहब बोले, बहन सरला जी बोली तब मैं बीच में नहीं बोला, मैं सुनता रहा। अब थोड़ी मेहरबानी मुझ पर हो जाये, नजरे-इनायत हो जाये और मुझे बोलने दें। आपने हमारी जितनी लानत-मलामत करनी थी वह आपने कर ली कि पता नहीं क्याबजट है, हम वैश्वीकरण के दबाव में आ गए, अन्तर्राष्ट्रीय दबाव में आ गए, हम कौन-कौन से दबाव में आ गए लेकिन फिर भी हम सरकार में बैठे हैं। बहन सरला जी का बस चले तो हमें समुद्र में उठाकर फैंक दें। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : भारत की जनता चाहती है। ...**(व्यवधान)**...

श्री सुन्दर लाल पटवा : भारत की जनता जो चाहती है वह कर रही है। ...**(व्यवधान)**...

***मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी** : सर, दूध की बात करिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सुन्दर लाल पटवा : आप बात करने दें, तो करूं। ...**(व्यवधान)**...

SHRI VAYALAR RAVI: The people of India don't want you to increase the price of milk. ...*(Interruptions)*...

श्री सुन्दर लाल पटवा : इसलिए मेरी प्रार्थना है कि एक विसंगति को दूर किया गया है । इससे जो दूध के कम दामों के कारण इसका दुरुपयोग हो रहा था, लोग गलत प्रकार से उपयोग करके इसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे, उस पर रोक लगी है । हम तो दिल्ली दुग्ध योजना को दिल्ली सरकार को सौंपना चाहते थे, वह इसी कारण इसे नहीं ले रहे थे कि आपकी इस विसंगति के कारण यह घाटा हम उठाने को तैयार नहीं हैं। 4 लाख लीटर दूध पर इतना घाटा उठाया जाए और 26 लाख लीटर दूध खुले आम 14 रुपये के दाम पर बिकने दिया जाए, इस विसंगति को दूर करने का सरकार ने प्रयास किया है, सोच-समझकर किया है। इसमें गरीबों के बच्चों के मुंह का निवाला छीनना, माताओं का दर्द - हमारी भी माताएं हैं, आपकी भी हैं - दर्द सभी का एक जैसा होता है और हम कोई दर्द देने के लिए यहां नहीं बैठे हैं । इसमें उस विसंगति को दूर करने का प्रयास किया गया है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को इससे सहमत होना चाहिए कि जो एक गलती चली आ रही थी - कौन सी सरकार थी, कौन सी नहीं थी, मैं इसके झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। ...**(व्यवधान)**...

---

* Transliteration of the speech in Persian Script is available in the Hindi Version of the Debates.

श्री जीवन राय (पश्चिमी बंगाल): गरीब लोगों ने दूध पीना छोड़ दिया इसीलिए चार से दो गाड़ियां हो गयीं''। ...**(व्यवधान)**...

***मौलाना ओबेदुल्ला खान आज़मी** : सर, जब प्याज़ महंगा हुआ था तब सोमपाल साहब मिनिस्टर थे। उन्होंने मज़ाक में कहा था कि प्याज़ महंगा हो गया तो आप लोग प्याज़ खाना छोड़ दीजिए। सरकार इस बात को गंभीरता से ले। यह बड़ा अहम मसला है। इसलिए हम फिर से मिनिस्टर साहब से रिक्वैस्ट करेंगे कि इसमें जो वृद्धि हुई है, इसको वापिस लेकर लोगों की बेचैनी खत्म करें। ...**(व्यवधान)**...

श्री सुंदर लाल पटवा : सर, यह एक विसंगति को दूर करने का प्रयास है, इसको वापिस लेने का प्रश्न नहीं है। जो गड़बड़ी हो रही थी, उसे ठीक करने का प्रयास किया गया है, माननीय सदस्यों को इस पर अपनी सहमति देकर इसको स्वीकार करना चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री वायालार रवि : यह क्या अनॉमलि हुई? यह कोई अनॉमलि नहीं है । ...**(व्यवधान)**...

***मौलाना ओबेदुल्ला खान आज़मी** : कोई विसंगति नहीं है, हम सब प्रोटैस्ट करते हैं। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: The House is adjourned till 2 o'clock.

The House then adjourned for lunch at fifty-seven minutes past twelve of the clock.

The House reassembled after lunch at four minutes past two of the clock, [THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI) in the Chair.]

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Karnataka): Sir, whenever you come to preside over the House, I am not able to understand why everybody starts enjoying.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): It is welcome.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Sir, we enjoy your presence. But he is envious of you.

---

* Transliteration of the speech in Persian Script is available in the Hindi Version of the Debates.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I am not envious at all.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANTAN BISI) : Now, let us take up the Supplementary Demands for Grants (General), 1999-2000.

Supplementary Demands for grants (General), 1999-2000

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Sir, I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) showing the Supplementary Demands for Grants (General), 1999-2000 (March, 2000).

SHORT DURATION DISCUSSION

Role of Governers in discharging their Constitutional responsibilities in the formation of Governments in the States in light of recent events in Bihar

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Now, we will take up Short Duration Discussion. Shri Pranab Mukherjee.

श्री रामदेव भंडारी (बिहार) : श्रीमन्, मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): पोइंट ऑफ ऑर्डर का है क्या ? बोलिए बोलिए ।

श्री रामदेव भंडारी: रूल 170 के तहत बिहार पर बहस के लिए नोटिस दिया गया था और अध्यक्ष जी ने उसका एडमिशन किया था और लीडर ऑफ दि हाउस ने आश्वासन दिया था कि सोमवार को इस पर बहस होगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसी रूल 170 के तहत इस पर बहस कराई जाए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आपके पास कोई कागज है कि लीडर ऑफ दि हाउस ने कांसेन्ट दिया है ।

श्री रामदेव भंडारी : वह तो प्रोसिडिंग में है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Let us see the proceedings. लाइये, लाइये ।

श्री रामदेव भंडारी : सोमवार को बहस होनी है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): देखिए, मैं देख रहा हूं ।